गुजरात में सूखे की स्थिति

4834. श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के विभिन्न जिलों में बड़े पैमाने पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा स्थिति से निपटने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अन्तर्गत कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) (श्री उत्तमभाई एच. पटेल): (क) जैसा कि राज्य सरकार ने सूचित किया है गुजरात के किसी भी जिले में सूखे की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है।

(ख) व (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 1994-95 के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा मुहैया करायी गई जिलावार वित्तीय सहायता नीचे दी गई है:

	जिला	केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये में)
1.	अहमदाबाद	30.50
2.	अमरेली	107.75
3.	भावनगर	41.50
4.	जामनगर	28.35
5.	कच्छ	106.75
6.	पंचमहल	100.75
7.	राजकोट	70.50
8.	सुरेन्द्रनगर	131.25
	जोड़:	617.35

Area brought under Wasteland Development Scheme in Haryana and UP

4835. DR. SANJAYA SINH: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Unstarred Question 1643 given in the Rajya Sabha on 23rd March, 1995 and state:

(a) The area of land brought under the Wasteland Development Scheme during the last three years in Haryana and U.P., district-wise; and

(b) the amount of funds allocated for the development of Wasteland, district-wise and the amount released for that purpose during the last three years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF WASTELANDS DEVELOPMENT): (COL. RAM SINGH): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

लघु सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा किया गया कार्य

4836. श्री शिव प्रसाद धनपुरिया: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 31 दिसम्बर, 1994 तक ग्राम पंचायतों द्वारा बनाये गए जलाशय और छोटे बांध या लगाए गये नलकूपों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्य वार कितने भूक्षेत्र की सिंचाई की जा रही है; और

(ग) ग्राम पंचायतों द्वारा 31 मार्च, 1994 तक इन छोटी सिंचाई परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) (श्री उत्तमभाई एच. पटेल): (क) से (ग) जवाहर रोजगार योजना में लघु सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा कार्य तथा सिंचाई हेतु ग्रामीण टैंकों / तालाबों के निर्माण के कार्य किए जाते हैं। दस लाख कुंओं की योजना में भी सिंचाई कुंओं के निर्माण का प्रावधान है जबकि जिला ग्रामीण विकास

एजेंसियां / जिला परिषद दस लाख कुंओं की योजना को सीधे कार्यान्वित करती हैं, ग्राम पंचायतें भी जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसी / जिला परिषद द्वारा उनको निर्धारित निधियों से लघु सिंचाई कार्य शुरू करती हैं। तथापि, भौतिक परिसम्पत्तियों, जैसे-जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सृजित लघु सिंचाई कार्यों की केन्द्र सरकार द्वारा निगरानी राज्य स्तर पर की जाती है।

लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर किए गए क्षेत्र, जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए ग्रामीण टैंकों और तालाबों तथा दस लाख कुंओं की योजना के अंतर्गत निर्मित कुंओं की संख्या तथा उन पर हुए खर्च से संबंधित ब्यौरे (राज्यवार) अनुपत्र। पर दिए गए हैं। [देखिये परिशिष्ट 173, अनुपत्र से 99]

Dilution of the Ceiling Provisions of Land Reforms Act in West Bengal

4837. SHRI JOYANTA ROY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of West Bengal have sought the permission for diluting the ceiling provision of its Land Reforms Act; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL) (a) The West Bengal Government have sought to introduce some exemptions to the land ceiling provisions of the Land Reforms Act.

(b) The matter is under consideration of the Government of India.

Employment to Rural Youth

4838. SHRI ISH DUTT YADAV:
CHAUDHARY HARMOHAN SINGH:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have not provided employment so far to those villages who were trained through self employment programme under the Integrated Rural Development Programme;

(b) if so, what are the reasons therfor and what are the details thereof;

(c) whether it is also a fact that Government have also not been able to provide employment to the rural youth; and

(d) what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) to (d) The Scheme— "Training of Rural Youth for Self-Employment (TRYSEM)" is being implemented throughout the country except Delhi and Chandigarh. It aims at providing technical and entrepreneurship skills to rural youth in the age group of 18-35 years from families below the proverty line to enable them to take up self employment, income-generating activities in the broad fields of agriculture -and allied sectors, services and industries. They also take up wage employment. Government does not provide, the employment on its own^but imparts skills to enable youth to earn livelihood. Large number of rural youth has thus got self or wage employment.

Assistance Provided to Assignees of Ceiling Surplus Land

4839. SHRI KANAKSINH MOHAN-SINH MANGROLA:
CHAUDHARY HARMOHAN SINGH:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any assistance is being provided to the assignees of ceiling surplus land under Centrally Sponsored Scheme;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the amount allocated to States